— Universalisation of Elementary Education; and

— Non-Formal Education.

The Total Literacy Campaign (TLC) is the principal strategy of NLM to eradicate illiteracy with a focus on women and disadvantaged groups. Under the literacy campaigns, 60% of the learners are women.

The Central and State Governments have taken several steps to promote education of girls. These include: establishment of separate schools for girls; provision of attendance scholarships; free textbooks and uniforms; exemption from tuition fee; appointment of more women teachers; and provision of separate toilets for girls. Under the Centrally Sponsored Scheme of Non-Formal Education, 90% Central assistance is provided to girls' centres. The proportion of girls' centres has been raised from 25% to 40% in the Eighth Plan. The introduction of the Mid-day Meals Programme is also expected to have a positive effect on enrolment and retention of girls in primary schools.

The National Agenda for Governance envisages free education for women upto College level.

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापकों की आधुनिकीकरण योजनाएं

1907. **श्री मोहम्मद मसूद खान:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यक संस्थाओं में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्यापकों के लिए आधुनिकीकरण योजना अस्तित्व में है;

(ख) यदि हां, तो उन अल्पसंख्यक मदरसों का ब्यौरा क्या है जो कि यह अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, तथा अनुदान की राशि कितनी-कितनी है; और

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी हां। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार मदरसा शिक्षा की आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना को कार्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष में एक बार अनुदान दिया जाता है, जो इसे आगे मदरसों को संवितरित करती है।

योजना के प्रमुख संघटक नीचे दिए गए हैं:—

(i) विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान और भाषाएं पढ़ाने के लिए अर्हताप्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों को 100% तक की वित्तीय सहायता।

(ii) मदरसों में इन विषयों के पुस्तक बैंक स्थापित करने और पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना।

(iii) विज्ञान/गणित के किटों और आवश्यक उपस्करों आदि का प्रावधान करना।

वर्ष 1997-98 के दौरान जिन अल्पसंख्यक समुदाय के मदरसों ने अनुदान प्राप्त किया है, उनकी सूची, तथा अनुदान की राशि संलग्न अनुपत्र में दी गई है। **[देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र संख्या 60]**

Dowry Deaths

1908. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Dowry Prohibition Act is ineffective to check approximately 5000 dowry deaths reported annually in the country;

(b) the recommendations made by the National Commission for Women to check dowry deaths; and

(c) the action taken on the recommendations?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) No, Sir.